केजरीवाल - बिजली के तार
भ्रष्टाचार और बेरोज़गार

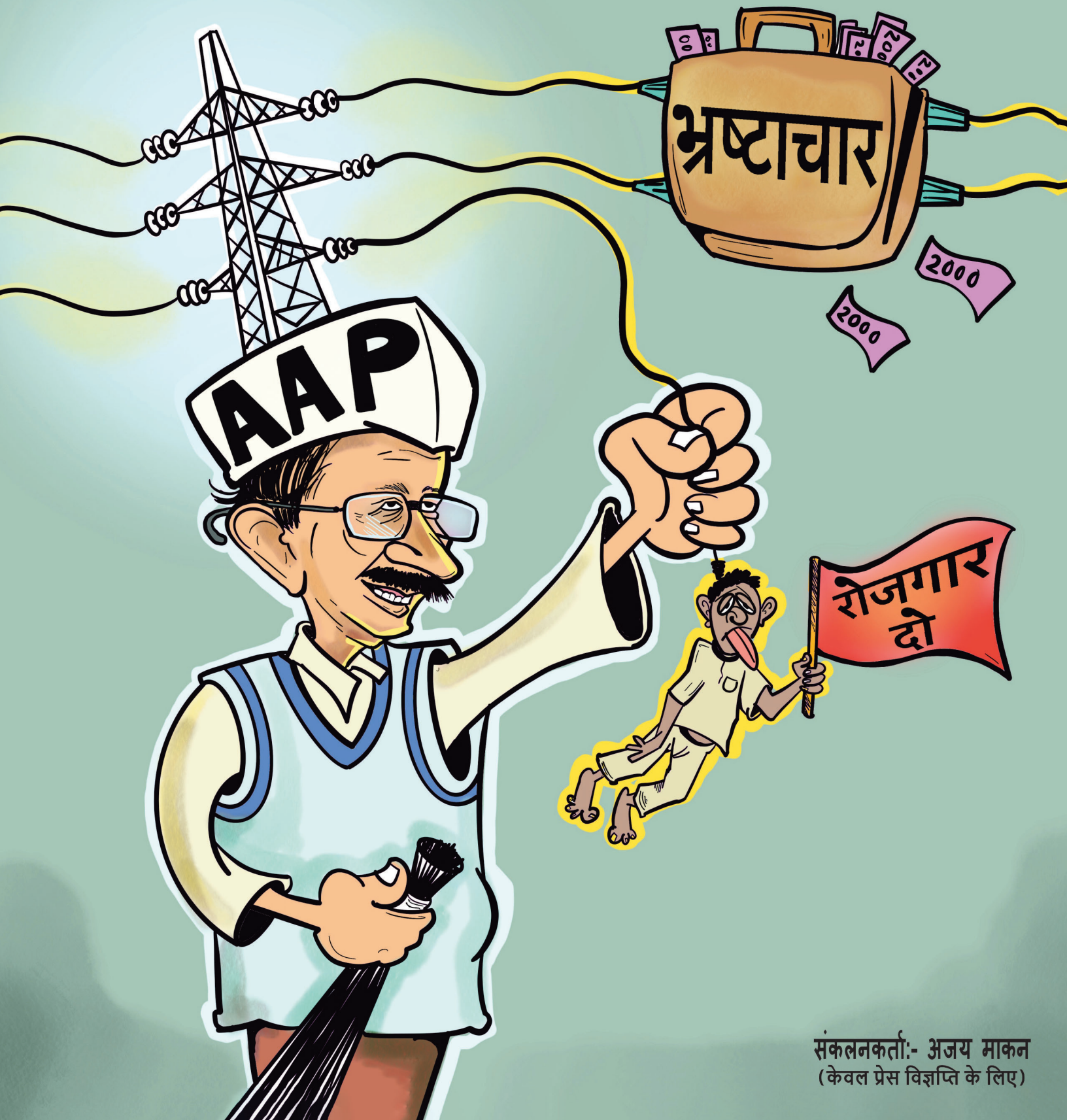

संकलनकर्ता:- अजय माकन
(केवल प्रेस विज्ञप्ति के लिए)

AFFIDAVIT

I, Ajay Maken, s/o Late Sh. C.P.Maken, resident of J-12/2 Rajouri Garden, New Delhi, do solemnly affirm as hereunder: -

1. Any data used in this booklet titled "केजरीवाल - बिजली के तार, भ्रष्टाचार और बेरोज़गार" have been drawn from publicly available sources on the website, and periodic reports of RBI (Reserve Bank of India), Government of India &its undertakings, Delhi Government &its undertakings DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission).

AJAY MAKEN

NOTARY PUBLIC SHIVELAL Regd No 2686/4 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
DELHI INDIA
2022

केजरीवाल - बिजली के तार

भ्रष्टाचार और बेरोज़गार

	पृष्ठ संख्या
चित्र 1 – औसत कमर्शियल मूल्य/यूनिट किलोवॉटघंटा	2
चित्र 2 – औसत औद्योगिक मूल्य/यूनिट 2020–21 (रु./किलोवॉटघंटा)	3
चित्र 3 – उद्योगवार रजिस्टर्ड फैक्ट्री एवं अनुमानित काम करने वाले कर्मचारी	3
चित्र 4 – 11 बड़े उद्योगों में कर्मचारी 2014 एवं 2019	4
चित्र 5 – 11 बड़े उद्योगों में फैक्ट्री 2014 एवं 2019	4
चित्र 6 – मैनुफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा जोड़ी गई ग्रॉस स्टेट वैल्यू में सीएजीआर	4
चित्र 7 – दिल्ली में कुल जीएसवीए (ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड) में मैनुफैक्चरिंग में %हिस्सा	5
चित्र 8 – दिल्ली में बिजली वितरण सेक्टर में एटीएंडटी नुकसान	6
चित्र 9 – बिजली क्षेत्र में 2020–21 एटीएंडटी (चोरी)	6
चित्र 10 – औसत मूल्य (प्राप्त हुआ राजस्व)/ यूनिट	6
चित्र 11 – दिल्ली एवं पड़ोसी राज्य औसत बिजली दर	7
चित्र 12 – दिल्ली बिजली मूल्य 2015 से 2021	7
चित्र 13 – बिजली सब्सिडी पर आप 2015 चुनावी घोषणापत्र	8
चित्र 14 – जीएनसीटीडी द्वारा प्राईवेट डिसकॉम्स को दी गई वार्षिक बिजली सब्सिडी राशि	8
चित्र 15 – मेरे आरटीआई आवेदन की प्रति, 29 अगस्त 2019	9
चित्र 16 – बिजली सब्सिडी के डीबीटी के लिए डीईआरसी का सुझाव	9
चित्र 17 – 2013–12 से कंज़्यूमर कैटेगरी वाईज़ डेटा सेल्स	10
चित्र 18 – कंज़्यूमर कैटेगरी वाईज़ उपभोग (मेगा यूनिट) 2013–14 से 2020–21	11

इस शोधपत्र में दिल्ली में केजरीवाल के मॉडल बिजली क्षेत्र के कारण उत्पन्न भारी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यह सब कितने बड़े पैमाने पर किया गया है।

2019–20 में, कोविड महामारी फैलने से पहले, दिल्ली में 30,432 मेगायूनिट बिजली बेची जाती थी, और **28,260 मेगायूनिट बिजली बेचकर 24,388.38 करोड़ रु. का राजस्व एकत्रित**

किया गया था। इस साल इससे भी ज्यादा राजस्व एकत्रित होगा। दिल्ली देश में एक मात्र राज्य है, जहाँ राज्य सरकार प्राईवेट कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। देश में किसी भी अन्य जगह सीधे प्राईवेट वितरण कंपनी को सब्सिडी नहीं दी जाती है। साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद **प्राईवेट वितरण कंपनियों को दिल्ली सरकार द्वारा बिना ऑडिट के और संदिग्ध तरीके से** कुल **14,731 करोड़ रु. की सब्सिडी दी जा चुकी है।** अकेले 2021–22 में इन प्राईवेट कंपनियों को 3090 करोड़ रु. दिए गए।

अ – व्यापक बेरोजगारी और दिल्ली से ऑफिसेज़ एवं उद्योगों का बड़ी संख्या में पलायन

दिल्ली में कमर्शियल और औद्योगिक दरों में भारी बढ़ोत्तरी

केजरीवाल के बिजली मॉडल ने औद्योगिक और कमर्शियल बिजली की दरों में भारी बढ़ोत्तरी कर दी है। औद्योगिक और कमर्शियल दरें, जो चित्र 1 और चित्र 2 में साफ दिखाई दे रही हैं, अभी तक देश में सबसे ज्यादा हैं, और इसी के कारण ऑफिस एवं उद्योग बड़ी संख्या में दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर व्यापक बेरोजगारी फैल रही है।

चित्र 1 में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में औसत **कमर्शियल दर** का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 16.09 रु. प्रति यूनिट की दर से दिल्ली में कमर्शियल बिजली का मूल्य सबसे ज्यादा है।

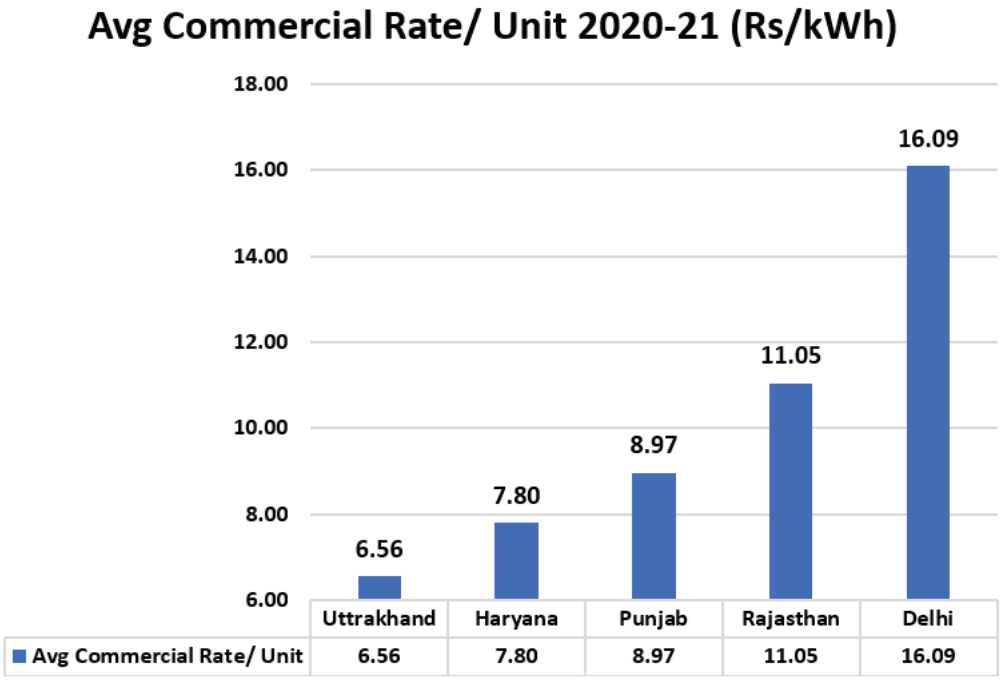

चित्र 1 – औसत कमर्शियल मूल्य/यूनिट किलोवॉटघंटा

नीचे चित्र 2 में दिल्ली एवं अन्य पड़ोसी राज्यों में औसत **औद्योगिक दरों** का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। 13.00 रु. प्रति यूनिट की दर से दिल्ली में औद्योगिक बिजली सबसे महंगी है।

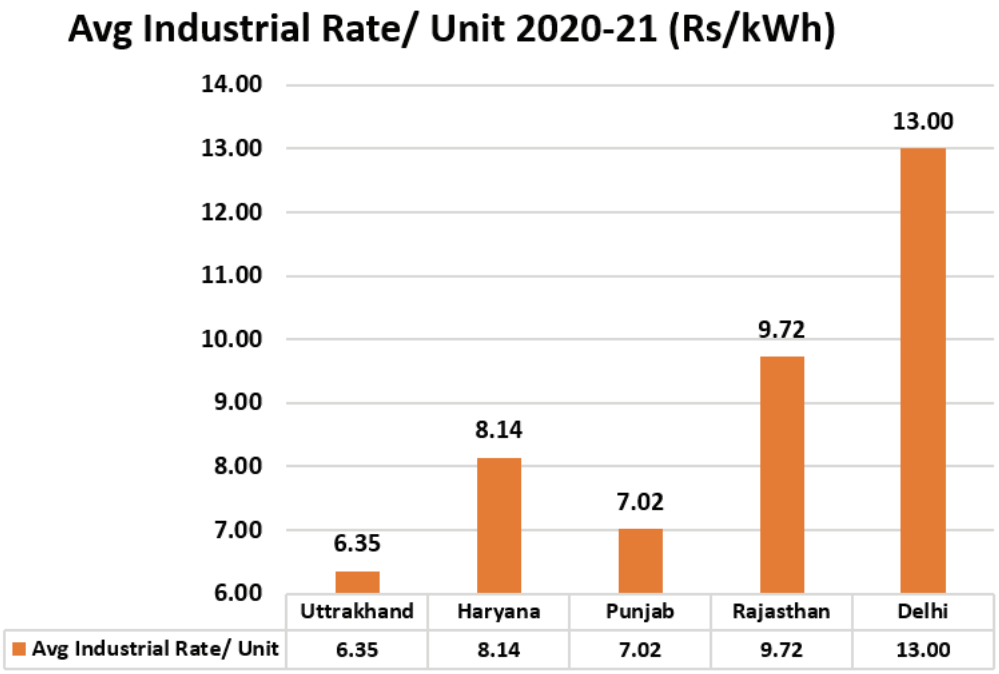

चित्र 2 – औसत औद्योगिक मूल्य/यूनिट 2020–21 (रु./किलोवॉटघंटा)

ऑफिस और उद्योगों का बड़ी संख्या में पलायन, जो फैला रहा दिल्ली में भारी बेरोजगारी

चित्र 3 में दिए गए चार्ट में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली से उद्योगों का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। चार्ट में इसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैंने दिल्ली में रोजगार का सृजन करने वाले 11 मुख्य कारखानों की सूची प्रस्तुत की है। ये कारखाने प्रदूषण न करने वाले छोटे एवं कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

INDUSTRY-WISE REGISTERED FACTORIES AND ESTIMATED WORKERS EMPLOYED

Industries	2014 Factories Nos	2019 Factories Nos	2014 Workers Nos	2019 Workers Nos
Food Product	330	142	20,316	8,894
Beverages, Tobacco and Tobacco Product	46	34	3,214	1,913
Textile Products	2,033	1,519	1,41,263	1,04,978
Wood products, Furnitures and fixtures	265	98	10,317	3,842
Paper and paper products Printing publishing & allied	765	587	29,816	22,600
Leather and leather fur products (except repair)	298	139	12,872	6,047
Chemical and Chemical products (except Petroleum & Coal)	295	173	11,793	7,048
Non-Metallic mineral products	82	11	2,426	151
Basic Metal and Alloy Industry	525	775	8,614	11,842
Metal products and Parts Machinery & Transport equipment-Machine tools including Electrical Appliances	1,913	757	76,427	30,007
Repair of Capital goods & Repair Services	540	219	30,502	12,441
Total	**7,092**	**4,454**	**3,47,560**	**2,09,763**

चित्र 3 – उद्योगवार रजिस्टर्ड फैक्ट्री एवं अनुमानित काम करने वाले कर्मचारी

साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद, अकेले इन 11 श्रेणियों में, 37 प्रतिशत यानि 2638 उद्योगों पर ताला लग चुका है, जिसके कारण इन कारखानों में काम करने वाले 40 प्रतिशत यानि 1.38 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

नीचे चित्र 4 और चित्र 5 बंद हुए कारखानों और बढ़ती बेरोजगारी को साफ कर रहे हैं।

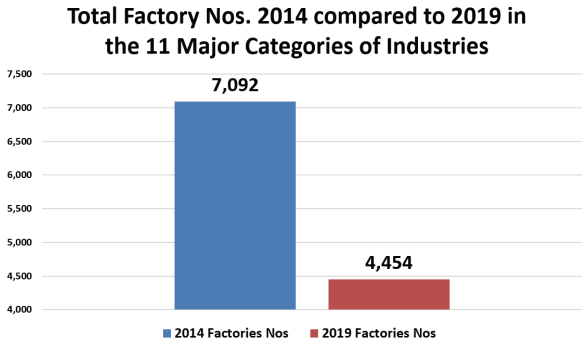

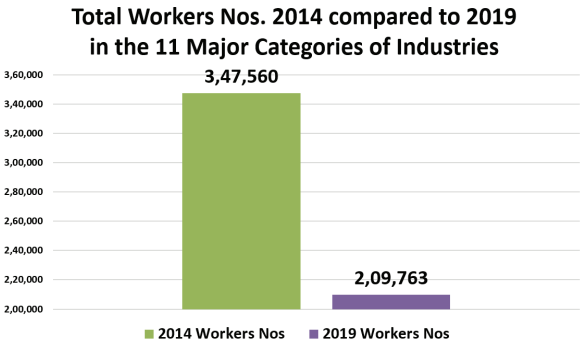

चित्र 4 11 बड़े उद्योगों में कर्मचारी 2014 एवं 2019 *चित्र 5 11 बड़े उद्योगों में फैक्ट्री 2014 एवं 2019*

दिल्ली का बढ़ता घाटा, पड़ोसी राज्यों को होता मुनाफा

चित्र 6 में दिया गया चार्ट राज्य की अर्थव्यवस्था में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा जोड़ी गई ग्रॉस स्टेट वैल्यू में कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) को दर्शाता है। यह सीएजीआर दो अवधियों के लिए दिया गया है; पहली नीली रेखा 2009–10 से 2013–14 के बीच की अवधि के लिए है, जब दिल्ली और केंद्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, और ऑरेंज रेखा 2015–16 से 2020–21 के लिए है, जब केंद्र में भाजपा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है।

यह ग्राफएक दिलचस्प पैटर्न प्रदर्शित कर रहा है कि दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के दौरान मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सीएजीआर (2009–10 से 2013–14 के बीच 5 सालों की अवधि के लिए) 11.93 प्रतिशत था, जो आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल (2015–16 से 2020–21) के बीच घटकर मात्र 0.74 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है क्योंकि दिल्ली से बाहर जाती कंपनियों के कारण पड़ोसी राज्यों में सीएजीआर में गिरावट काफी कम रही।

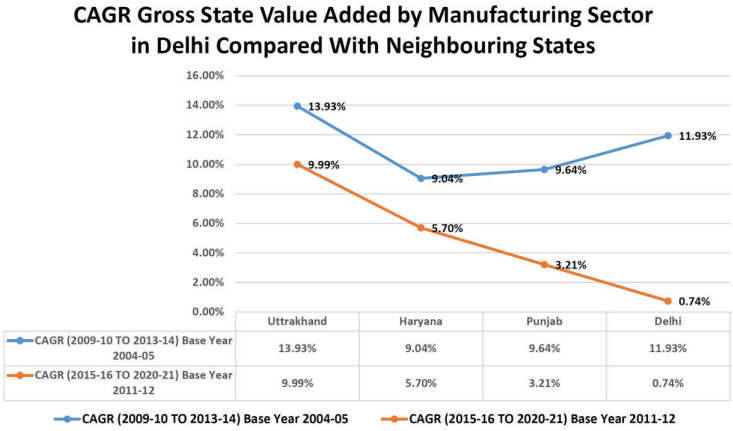

चित्र 6 मैनुफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा जोड़ी गई ग्रॉस स्टेट वैल्यू में सीएजीआर

दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर असर

केजरीवाल मॉडल का प्रभाव चित्र 7 में दिए गए चार्ट देखा जा सकता है। दिल्ली में कुल जीएसवीए (ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड) में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का प्रतिशत हिस्सा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार नीचे की ओर गिरता जा रहा है। **मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में प्रतिशत हिस्सा 2012–13 (कांग्रेस सरकार के आखिरी पूरे साल) में 6.82 प्रतिशत से नीचे गिरकर 2020–21 (आम आदमी पार्टी की सरकार) में 4.52 प्रतिशत रह गया, यानि कांग्रेस सरकार के समय के मुकाबले इसमें एक तिहाई से ज्यादा गिरावट हुई।**

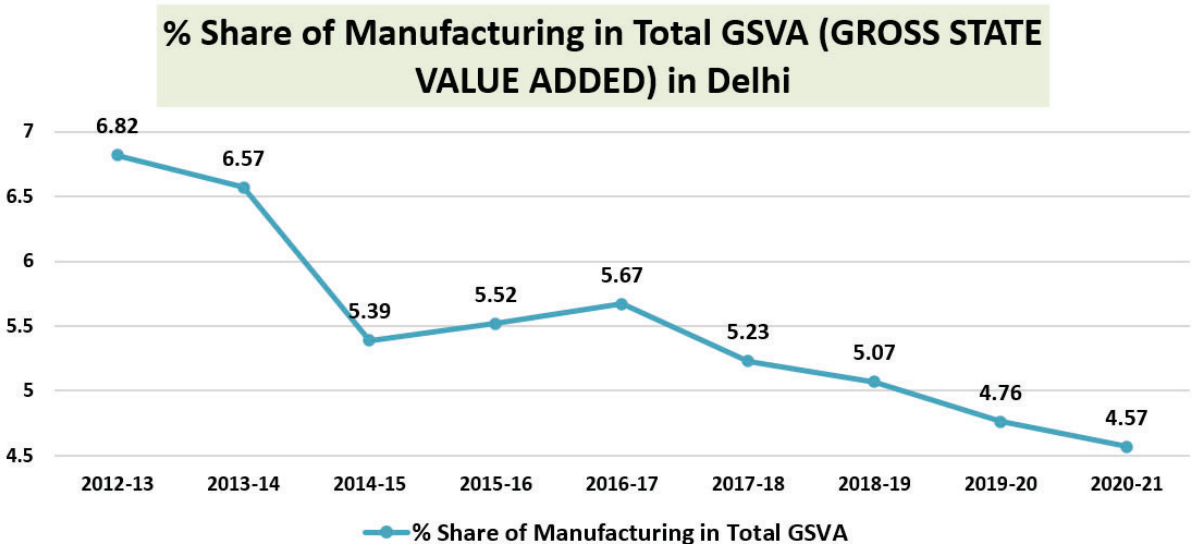

चित्र 7 दिल्ली में कुल जीएसवीए (ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड) में मैनुफैक्चरिंग में प्रतिशत हिस्सा

ब – केजरीवाल सरकार के बिजली मॉडल में भ्रष्टाचार का बोलबाला

चित्र 8 में दिया गया चार्ट 2001 में एसबीआई कैप्स से लिया गया है। एसबीआई कैप्स कांग्रेस के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिजली सुधार के लिए कंसल्टैंट था। 2002 में प्राईवेटाईज़ेशन के समय, कुल AT&C (बिजली चोरी से) नुकसान लगभग 54 प्रतिशत था। कांग्रेस सरकार में, प्राईवेटाईज़ेशन के बाद, यह नुकसान 2013–14 में घटकर 16.19 प्रतिशत तक आ गया, जिसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में 2020–21 में बिजली की चोरी 16.19 प्रतिशत से घटकर 8.87 प्रतिशत रह गई, यानि बिजली चोरी में 7.32 प्रतिशत (चित्र 9) की गिरावट हुई। आज दिल्ली में देश में सबसे कम बिजली की चोरी होती है। 2019–20 के आँकड़ों के मुताबिक, **AT&C नुकसान का हर प्रतिशत हिस्सा 265.84 करोड़ रु. के बराबर होता है। अब सवाल यह है कि देश में जिस राज्य में सबसे कम AT&C (बिजली चोरी से होने वाला) नुकसान होता है, वहाँ बिजली की दर सबसे ज्यादा क्यों? यदि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान AT&C नुकसान में होने वाली 7.32 प्रतिशत की कमी को लिया जाए, तो इससे अकेले पिछले साल सरकार को 1.746 करोड़ रु. की अतिरिक्त कमाई हुई है। तो फिर बिजली दर में बढ़ोत्तरी क्यों?**

(%)

	AT&C Loss	Technical Losses	Non-Technical Losses
Central East	61.1	7.5	53.5
South West	52.1	8.5	43.6
North North West	49.5	9.9	39.5
Total	53.9	8.6	45.3

चित्र 8 दिल्ली में बिजली वितरण सेक्टर में एटीएंडटी नुकसान

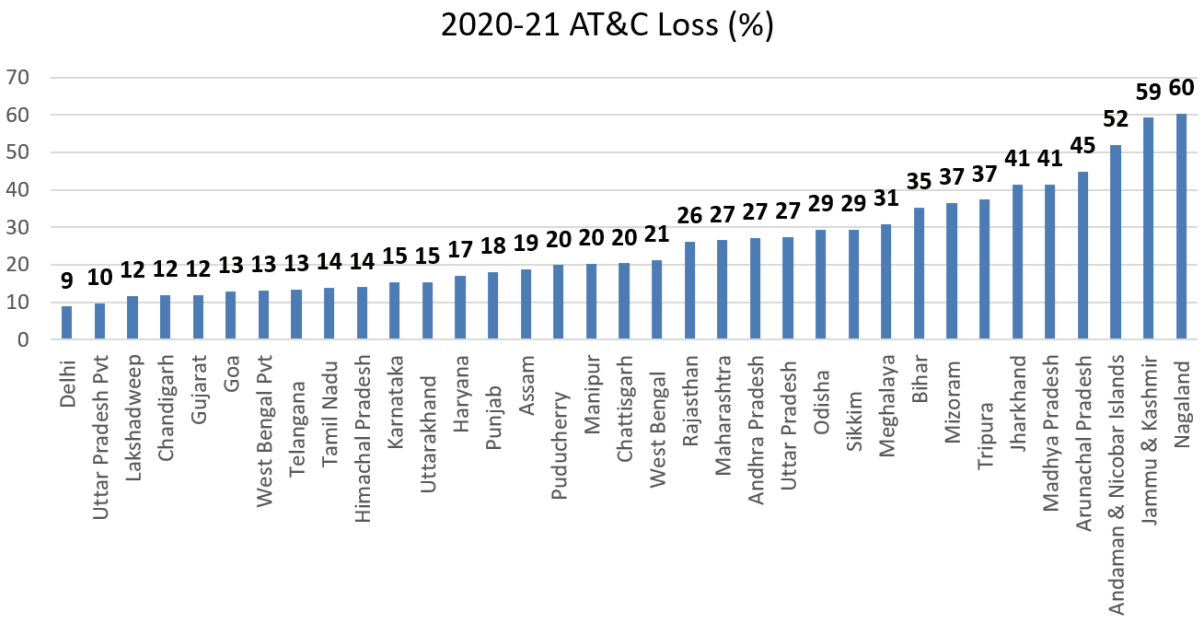

चित्र 9 बिजली क्षेत्र में 2020–21 AT&C (चोरी)

दिल्ली में बिजली का मूल्य देश में सबसे ज्यादा है। चित्र 10 में दिया गया चार्ट देखिए। 2020–21 में हर यूनिट के लिए औसतन 8.67 रु. के साथ दिल्ली में बिजली का मूल्य देश में सबसे ज्यादा है।

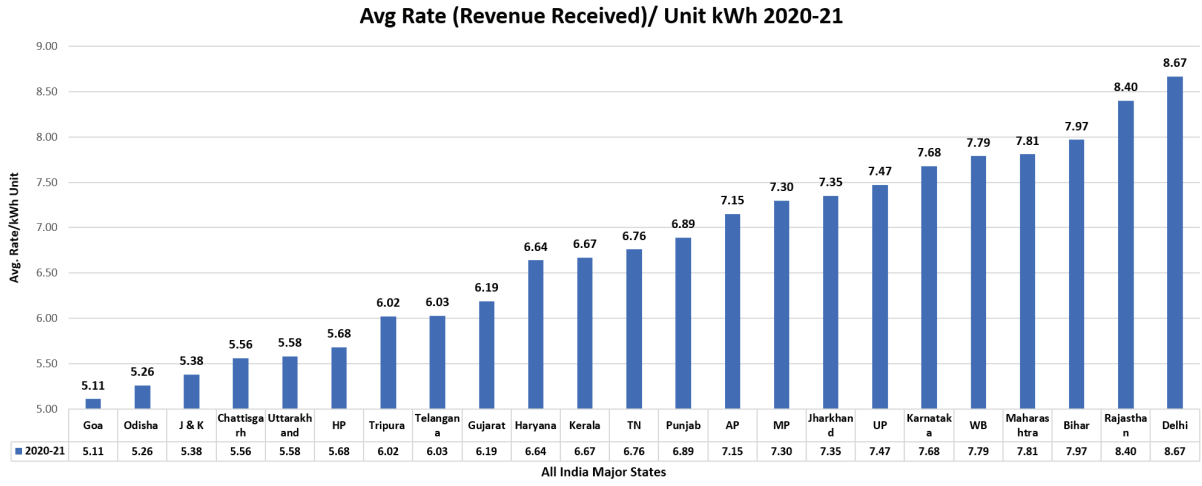

चित्र 10 औसत मूल्य (प्राप्त हुआ राजस्व)/ यूनिट

यदि हम पड़ोसी राज्यों से इन मूल्यों की तुलना करें, तो 8.67 रु. प्रति यूनिट की औसत बिजली के साथ दिल्ली में बिजली का मूल्य सबसे ज्यादा है।

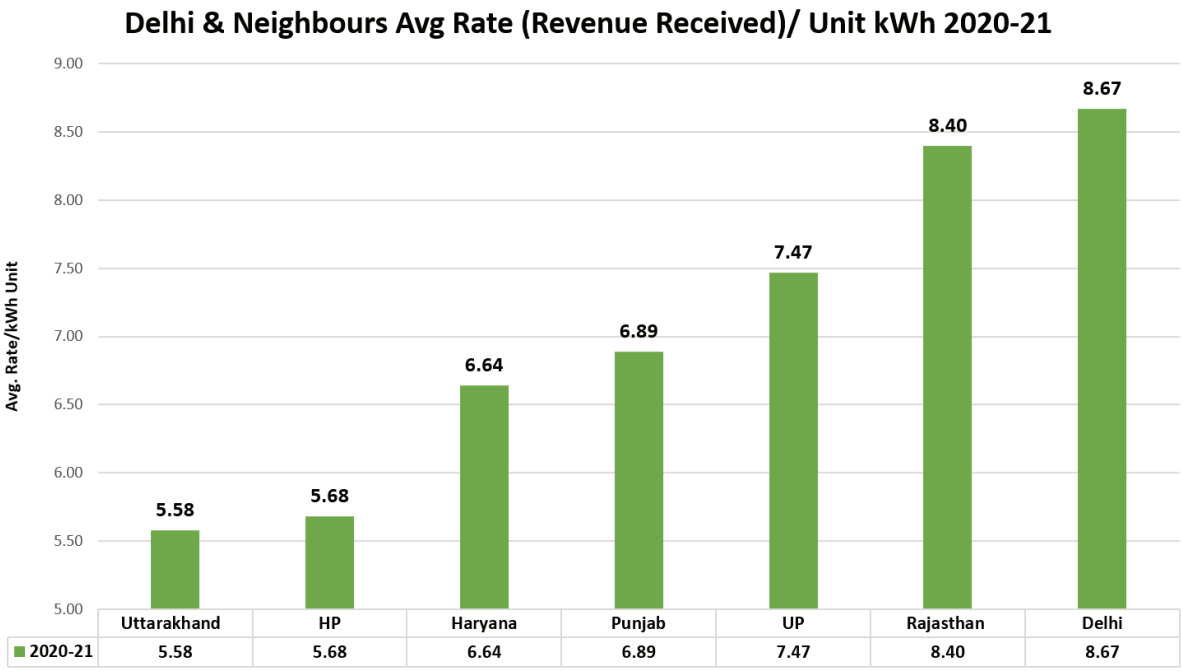

चित्र 11 दिल्ली एवं पड़ोसी राज्य औसत बिजली दर

जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब बिजली का औसत मूल्य 6.22 रु. प्रति यूनिट था। 2020–21 में यह 39 प्रतिशत बढ़कर 8.67 रु. प्रति यूनिट हो गया, वो भी तब, जब इस दौरान बिजली चोरी में भारी गिरावट हुई। साल–दर–साल औसत मूल्यों के लिए चित्र 12 में दिया गया चार्ट देखिए।

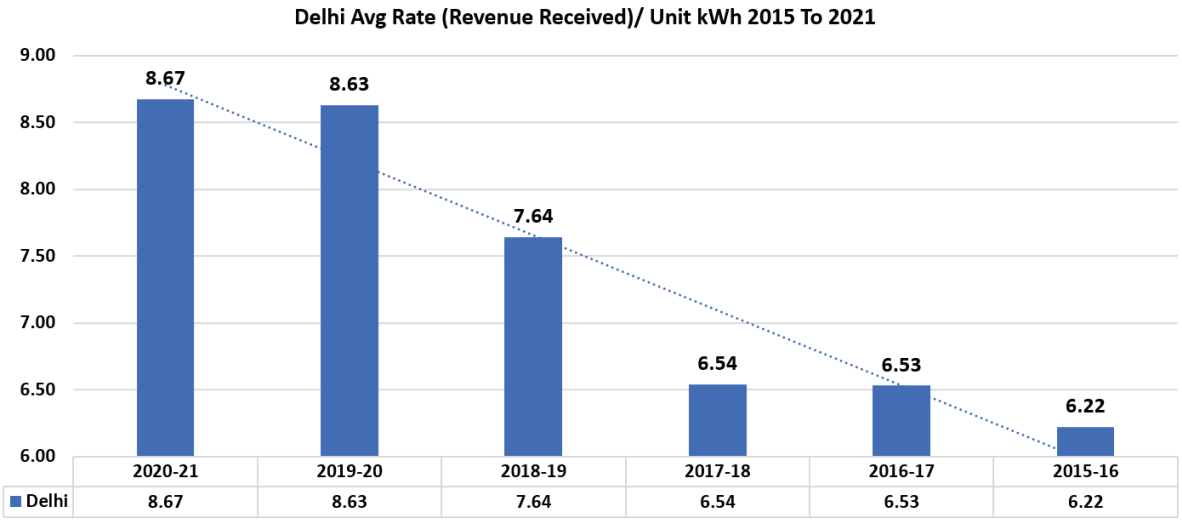

चित्र 12 दिल्ली बिजली मूल्य 2015 से 2021

स – संदिग्ध और भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी का बिजली का मॉडल

2015 में दिल्ली के आम चुनावों से पहले, आम आदमी पार्टी ने अपने 70 प्वाईंट एजेंडा में कहा, ***"... शुरू में हम सब्सिडी देंगे, जो पॉवर डिसकॉम्स को नहीं जाएगी, बल्कि राज्य के स्वामित्व की ट्रांसमिशन कंपनी, दिल्ली ट्रांसको को जाएगी..."***

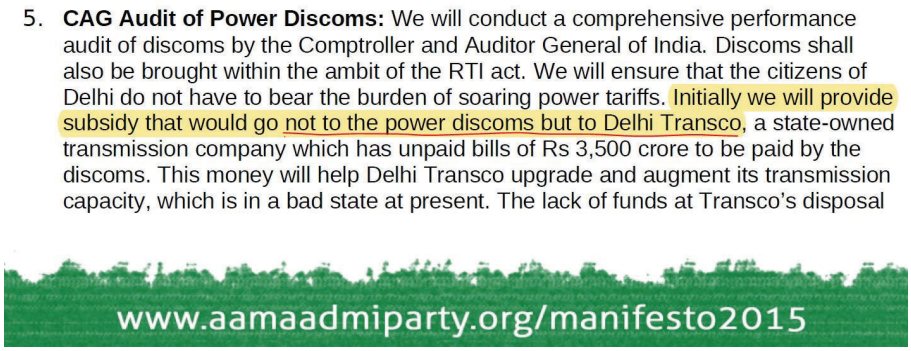
5. **CAG Audit of Power Discoms:** We will conduct a comprehensive performance audit of discoms by the Comptroller and Auditor General of India. Discoms shall also be brought within the ambit of the RTI act. We will ensure that the citizens of Delhi do not have to bear the burden of soaring power tariffs. Initially we will provide subsidy that would go not to the power discoms but to Delhi Transco, a state-owned transmission company which has unpaid bills of Rs 3,500 crore to be paid by the discoms. This money will help Delhi Transco upgrade and augment its transmission capacity, which is in a bad state at present. The lack of funds at Transco's disposal

चित्र 13 बिजली सब्सिडी पर आप 2015 चुनावी घोषणापत्र

लेकिन चित्र 14 में दिए गए चार्ट से स्पष्ट है कि 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, **प्राईवेट वितरण कंपनियों को दिल्ली सरकार ने बिना कोई ऑडिट किए और संदिग्ध तरीके से 14,731 करोड़ रु. की सब्सिडी दे डाली।** अकेले 2021–22 में इन प्राईवेट कंपनियों को 3090 करोड़ रु. दिए गए।

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
BRPL	659	648	720	785	1069	1312	
BYPL	376	466	468	423	641	797	
TPDDL	419	438	457	493	670	801	
TOTAL	1454	1552	1645	1701	2380	2910	3090

चित्र 14 जीएनसीटीडी द्वारा प्राईवेट डिसकॉम्स को दी गई वार्षिक बिजली सब्सिडी राशि

साल 2019 में बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के बारे में पूछते हुए मैंने आरटीआई के तहत सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं के विवरण की मांग की। दुख की बात है कि आज तीन साल बीत जाने के बाद भी यह विवरण मुझे नहीं दिया गया है।

29th August, 2019

To,
The Public Information Officer
Office of the Chief Minister of Delhi

From:
Ajay Maken
J-12/2 Rajouri Garden
New Delhi – 110027
+91 9868180656
ajay.maken@inc.in

Subject: Seeking information under RTI Act, 2005

Sir/ Madam,

An amount of more than Rs. 8,500 crore (approximately) from the Taxpayers hard earned money has been given private *bijli* companies / DISCOMs after the Congress Government demitted office in the Government of NCT of Delhi i.e. after December 2013. The said amount has been purportedly released to the private companies to reimburse the electricity subsidy provided by the GNCTD to the consumers. Kindly supply me the following information in this regard:

1) A complete list of month-wise beneficiaries/ consumers, along-with meter/connection number, of all those consumers who have received subsidy post December, 2013 i.e. when AAP formed Government for the first time. Also provide the latest list, till date, along with the details of amount and units of subsidy extended to such users.

2) Kindly give all papers/ sanction orders and details of year-wise grants/ amount released to private *bijli* companies / DISCOMs, post December 2013.

DECLARATION:
I state that the information sought does not fall within the restriction contained in Section 8 & 9 of the RTI Act and to the best of my knowledge it pertains to your office.

A fee of Rs. 10 is being sent through Postal Order, along-with this application, in the office of the Competent Authority vide P.O. No. 47F 232396 dated 29th August, 2019 .

Please rush information by registered post. This applicant is an Indian citizen. Kindly reply in English.

Permit me inspection of relevant records, with an assistant of my choice.

Sincerely,
Ajay Maken 29/08/19
Ajay Maken
New Delhi

चित्र 15 मेरे आरटीआई आवेदन की प्रति, 29 अगस्त 2019

19 फरवरी, 2018 को डीईआरसी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं को सब्सिडी के डीबीटी (डायरेक्ट ट्रांसफर) पर विचार करने के लिए कहा, ताकि ऑडिट की कोई जरूरत न रहे।

4. It may be stated that since release of subsidy is carried out by GoNCTD to DISCOMs, hence GoNCTD may consider to transfer of subsidy to the beneficiaries as is already being done by Govt in the matter of distribution of LPG subsidy. This will obviate the need for conducting any audit.

5. This issues with the approval of the Commission.

Yours Faithfully,
(Mahender Singh)
Executive Director (Tariff)

19/02/2018

चित्र 16 बिजली सब्सिडी के डीबीटी के लिए डीईआरसी का सुझाव

न तो प्राईवेट कंपनियों को दिए गए **14,731 करोड़ रु.** का ऑडिट कराया जा रहा है, और न ही दिल्ली सरकार उपभोक्ताओं को डीबीटी मिलने दे रही है। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं, तो और क्या है?

यदि डीबीटी का क्रियान्वयन कर दिया गया, तो इसी सब्सिडी के साथ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक बिजली निशुल्क हो जाएगी।

हितों का टकराव (कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट)

नवीन गुप्ता (आम आदमी पार्टी के **कोषाध्यक्ष** और सांसद एनडी गुप्ता के पुत्र) को प्राईवेट डिसकॉम्स, बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड **(बीआरपीएल),** और अनिल अंबानी ग्रुप के स्वामित्व की बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड **(बीवाईपीएल)** के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यदि यह हितों का टकराव नहीं है, तो क्या है?

बिजली का कंज़्यूमर कैटेगरी उपयोग अस्पष्ट

चित्र 17 से प्रदर्शित होता है कि 2013–14 से आगे, एक तरफ, घरेलू उपभोग 38.25 प्रतिशत से बढ़कर 58.74 प्रतिशत हो गया, वहीं कमर्शियल उपयोग में 19.40 प्रतिशत से 16.79 प्रतिशत तक गिरावट हो गई, औद्योगिक उपयोग लगभग 10.28 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

यह बिना ऑडिट के कंज़्यूमर कैटेगरी के ब्रेकअप एवं प्राईवेट कंपनियों को अनियंत्रित रूप से दी गई सब्सिडी का परिणाम है।

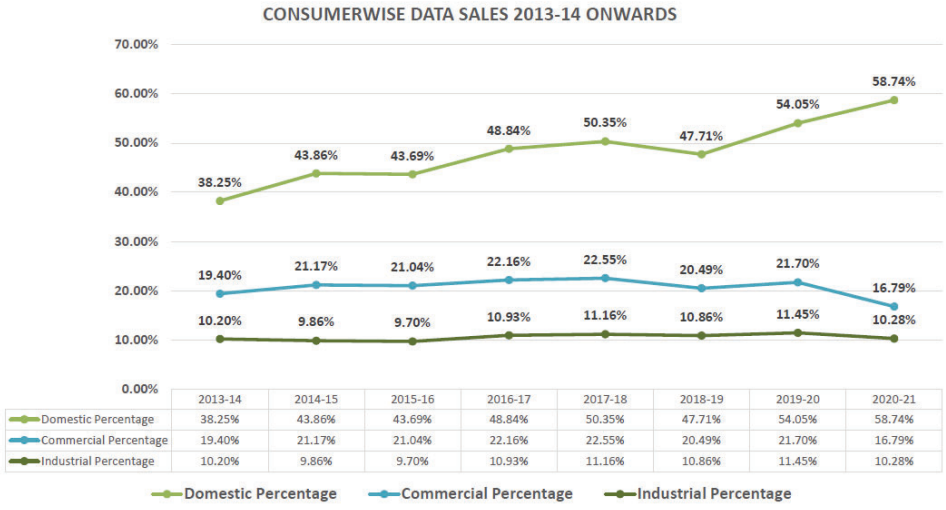

चित्र 17 2013–12 से कंज़्यूमर कैटेगरी वाईज़ डेटा सेल्स

बिना ऑडिट एवं संदिग्ध तरीके से निजी कंपनियों को सब्सिडी देने के परिणामस्वरूप इन कंपनियों ने उपभोक्ता श्रेणियों में बिजली के उपभोग में भारी परिवर्तन कर दिया।

कुल मेगायूनिट उपभोग का पैटर्न निम्नलिखित पैटर्न दर्शाता है।

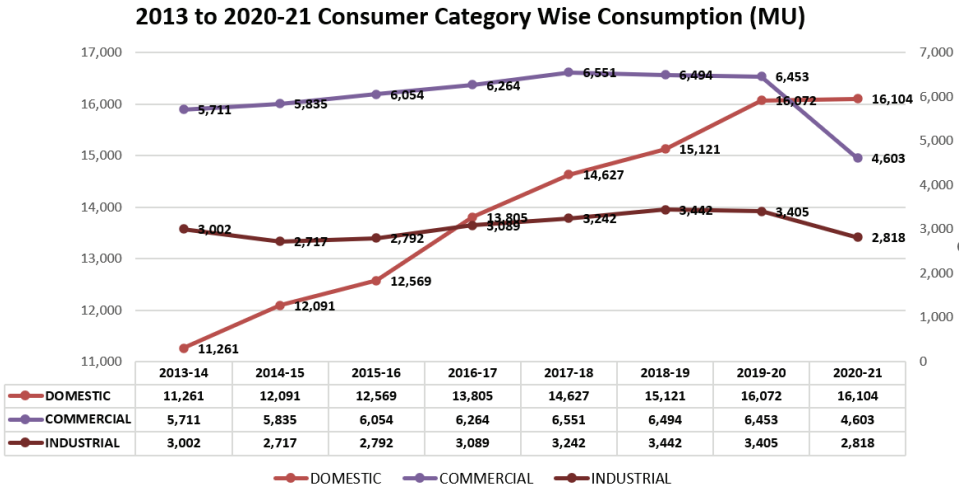

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
DOMESTIC	11,261	12,091	12,569	13,805	14,627	15,121	16,072	16,104
COMMERCIAL	5,711	5,835	6,054	6,264	6,551	6,494	6,453	4,603
INDUSTRIAL	3,002	2,717	2,792	3,089	3,242	3,442	3,405	2,818

चित्र 18 कंज़्यूमर कैटेगरी वाईज़ उपभोग (मेगा यूनिट) 2013–14 से 2020–21

प्राईवेट डिसकॉम्स की ओर से कंज़्यूमर कैटेगरी वाईज़ उपयोग को जानबूझकर इस तरह से रखा जा रहा है ताकि सरकार की ओर से उन्हें ज्यादा सब्सिडी मिल सके। सरकार बोर्ड में अपने प्रतिनिधि के साथ 49 प्रतिशत की अंशधारक है, तथा 14,731 करोड़ रु. की भारी सब्सिडी की राशि पर अपनी आँखें मूंदे हुए है, जो हर साल 3000 करोड़ रु. से ज्यादा बढ़ रही है।

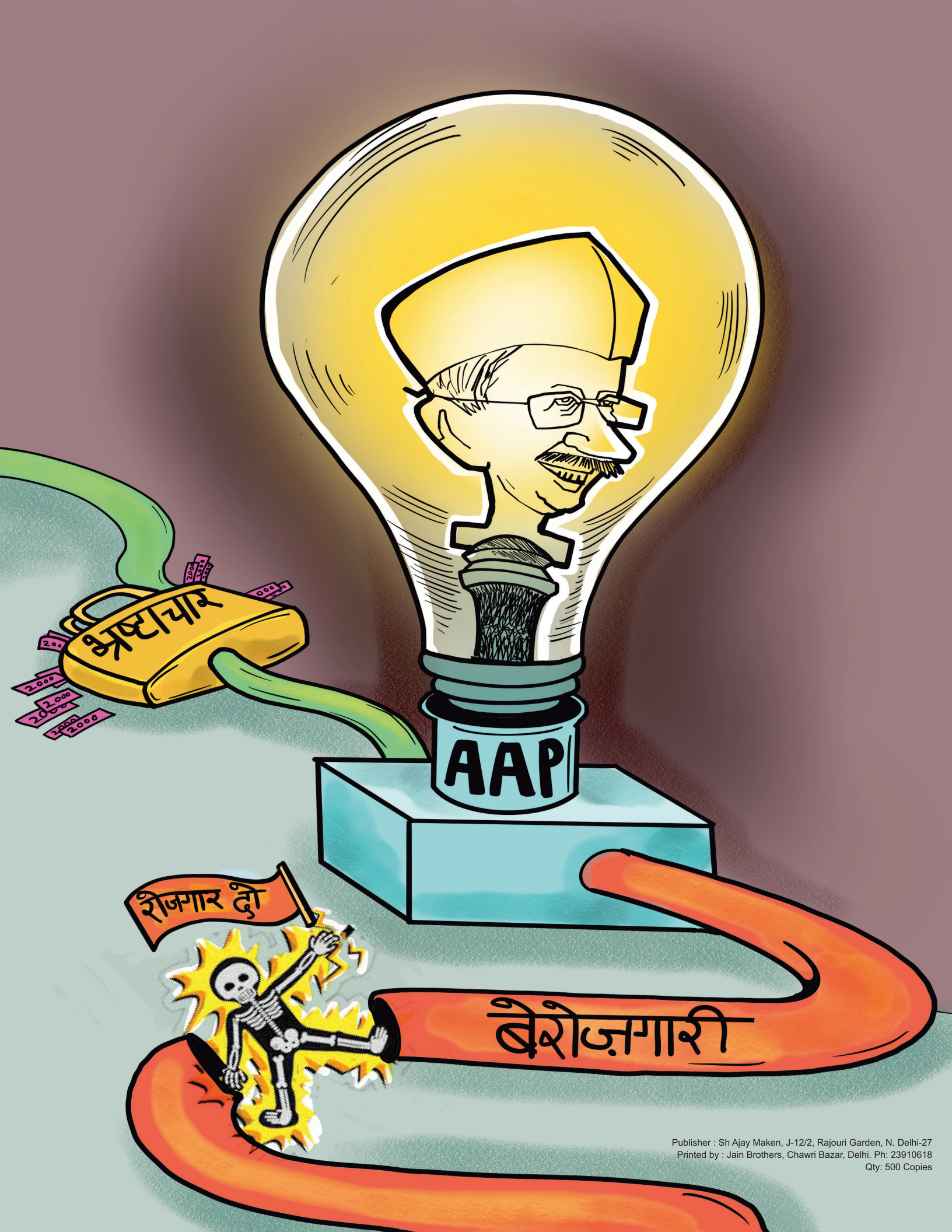

Publisher : Sh Ajay Maken, J-12/2, Rajouri Garden, N. Delhi-27
Printed by : Jain Brothers, Chawri Bazar, Delhi. Ph: 23910618
Qty: 500 Copies